शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 37 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 05 – 12 सितम्बर 2022 मूल्य पांच रूपए

क्यों बनी है शीर्ष प्रशासन में विस्फोटक स्थिति

- निशा सिंह के पत्र और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया से उठी चर्चा
- जब मुख्यमंत्री से न्याय न मिले तो क्या राज्यपाल से दखल की गुहार लगाना अपराध है
- जब सरकार केंद्र और अपने ही निर्देशों की अनदेखी करें तो क्या विकल्प रह जाता है

शिमला/शैल। जब मुख्यमन्त्री को सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को अपनी सीमा में रहने के लिए कहना पड़े और मुख्य सचिव से भी वरिष्ठ अधिकारी को प्रदेश के राज्यपाल से दखल देने की गुहार लगानी पड़ जाये तो यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रशासन के शीर्ष पर हालात बहुत ही विस्फोटक बन चुके हैं। ऐसा विस्फोट चुनावी बेला में राजनीतिक नेतृत्व के लिये कितना घातक हो सकता है इसका अंदाजा लगा पाना भी आसान नहीं होगा। क्योंकि जब वरिष्ठ अधिकारियों को भी राजनीतिक नेतृत्व से न्याय न मिल सके तो उसका सन्देश प्रशासन के सबसे अंतिम पायदान और जनता तक सुखद नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब राजनीतिक नेतृत्व किन्ही कारणों से एक वर्ग विशेष से ही घिर कर रह जाता है और दस्तावेजी परमाणों को भी नजरअन्दाज करके एक पक्षीय राय बना लेता है। आईएएस सेवा देश की शीर्षस्थ सेवा है और इसके शीर्ष पर पहुंचे अधिकारियों का भी अपना एक मान सम्मान होता है। यही अधिकारी होते हैं जिन्हें नियमों कानूनों की जानकारी राजनीतिक नेतृत्व से निश्चित तौर पर अधिक होती है। कई बार जो अधिकारी किन्ही कारणों से राजनीतिक नेतृत्व से ज्यादा नजदीक हो जाते हैं वह अपने स्वार्थो से प्रभावित होकर राजनीतिक नेतृत्व को गुमराह करने में सफल हो जाते हैं। ऐसा करने के लिये नेतृत्व के सामने नियमों कानूनों की सही और पूरी जानकारी नही रखी जाती है और नेतृत्व में यह क्षमता नही रह जाती है कि वह अपने स्तर पर सही तथा निष्पक्ष जानकारी जुटा सके। ऐसी स्थिति में जब ऐसे प्रशासनिक अधिकारी अपने स्वार्थो के कारण अपने वरिष्ठों का भी अहित करने पर आमदा हो जाते हैं तब प्रशासन के शीर्ष पर हालात ऐसे विस्फोटक हो जाते हैं। इस समय जयराम ठाकुर का शीर्ष प्रशासन शायद इसी दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री को नियमों कानूनों की सही जानकारी ही नहीं दी जा रही है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि नियमों कानूनों की अनुपालना ही नहीं होने दी जा रही है। क्योंकि इससे नुकसान प्रशासनिक नेतृत्व की बजाये राजनीतिक नेतृत्व का होता है। अभी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह जिस तरह से रुका उसके छिंटे प्रशासन पर न पढ़कर राजनीतिक नेतृत्व पर पड़े। इसके बाद यही फजीहत पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र के मुख्य सुरक्षा अधिकारी रह चुके पदम ठाकुर की पुनर्नियुक्ति के मामले में हुई। क्योंकि इन्हीं पदम ठाकुर के खिलाफ भाजपा के आरोप पत्र में गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इस वस्तुस्थिति की मुख्यमंत्री को जानकारी भी थी या नहीं यह सब गौण हो गया और नेतृत्व की फजीहत बड़ा मुद्दा बनकर चर्चित हो गयी।

ठीक आज यही स्थिति निशा सिंह के वायरल हुए पत्र के बाद उभरी है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री को लिखे पत्र का भी सही से जवाब न आये तो इतने बड़े अधिकारी के पास राज्यपाल से मामले में दखल देने की गुहार लगाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। इस समय प्रशासन के शीर्ष पर जिस तरह की विस्फोटक स्थिति बनी हुयी है उसका एक ही कारण है कि कुछ लोगों को अनुचित लाभ देने के लिये उन नियमों/निर्देशों की अनुपालना तक नहीं हो रही है जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन तक पर लागू हैं। यहां तक चर्चाएं बाहर आ रही हैं कि यूपीएससी में फेल होने को भी योग्यता बना दिया गया है। निश्चित तौर पर ऐसा न तो मुख्यमंत्री की जानकारी में होगा और न ही उनके निर्देशों से हुआ होगा। लेकिन यह सब उन्हीं के कार्यकाल में नियमों को संशोधित करके अंजाम दिया गया है तो निश्चित रूप से उन्हीं के नाम लगेगा। ऐसे में यदि अभी भी जयराम प्रशासन केंद्र सरकार और अपने निर्देशों की अनुपालन नहीं कर पाता है तो पूरी स्थिति विस्फोटक हो जायेगी। उसमें कुछ भी बचना संभव नहीं रह पायेगा।

भारत सरकार के निर्देश जिनकी अनुपालना नही हुई

8. As regards the stage when prosecution for a criminal charge can be stated to be pending, the said O.M. dated 14.9.92 dose not specify the same and hence the definition of pendency of judicial proceedings in criminal cases given in Rule 9 (6)(b)(i) of CCS (Pension) Rules, 1972 is adopted for the purpose. The rule 9 (6)(b)(i) of CCS (Pension) Rules, 1972 provides as under:-

"(b) judicial proceedings shall be deemed to be instituted-

(i) In the case of criminal proceedings, on the date on which the complaint or report of a Police Officer, of which the Magistrate takes cognizance, is made".

राज्य सरकार के निर्देश जिनकी अनुपालना नही हुई

3. Keeping in view the above instructions of Government of India, alteration is required to be effected in the procedure being followed in the State for issuance of Vigilance Clearance Certificates, so that the same are consistent with the guidelines of the Supreme Court of India. Accordingly, after due consideration it has been decided to substitute the provision of Para 6.4 of Chapter-II of Himachal Pradesh Vigilance Manual with the following-

6.4 " The vigilance clearance certificate will not be issued by the Vigilance Department or the competent authority as the case may be in respect of a Government servant if-

1. **He/she is under suspension; or**
2. **In respect of whom a charge sheet has been issued and the disciplinary proceedings are pending; or**
3. **Against whom prosecution for a criminal charge is pending.**

NOTE:- As regards the stage when prosecution for a criminal charge can be stated to be pending, the Rule-9(6)(b)(i) of CCS (Pension) rules, 1972 shall be followed which provides as under:

"(b) Judicial proceedings shall be deemed to be instituted:-

(i) In the cases of criminal proceedings, on the date on which the complaint or report of a Police Officer, of which the Magistrate takes cognizance, is made"

But the vigilance clearance certificate will be issued by the competent authority or the Vigilance Department as the case may be in respect of a Government servant in all other cases.

राज्यपाल ने 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' में लिया भाग

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' के शुभारम्भ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) में भारत की त्वरित प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। इस समारोह में राष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, समुदाय के नेताओं और नागरिकों के अथक प्रयासों की सराहना की और टीबी उन्मूलन के लिए भी इसी तरह का सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के राज्यपालों द्वारा टीबी मुक्त भारत की दिशा में की गई पहलों को प्रदर्शित करती वीडियो फिल्म भी दिखाई गई।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार के अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रीं, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल-उपराज्यपाल, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रीं और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। वर्चुअल कार्यक्रम में राज्यों और जिलो के स्वास्थ्य अधिकारी, उद्योग जगत और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ टीबी चौंपियंस ने भी भाग लिया तथा इस उच्च संक्रामक रोग के उन्मूलन के लिए निर्धारित किए गए वैश्विक लक्ष्य 2030 को पांच वर्ष पहले ही यानि वर्ष 2025 तक हासिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

राष्ट्रपति ने टीबी उपचार के संबंध में अतिरिक्त निदान, पोषण और व्यावसायिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए निक्षय मित्र पहल की भी शुरुआत की। उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों को दान दाताओं के रूप में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि मरीजों को स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिल सके।

निक्षय 2.0 पोर्टल (https://communitysupport.nikshay.in/) टीबी के मरीजों के उपचार के परिणामों में सुधार के लिए अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करेगी तथा वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का लाभ उठाते हुए भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में मददगार साबित होगा।

राज्यपाल ने शिमला प्रेस क्लब के पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। प्रेस क्लब शिमला ने अनाडेल शिमला के निकट ग्लेन में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने देवदार का एक पौधा रोपित किया। इस अवसर पर क्लब के सभी सदस्यों, क्षेत्र के प्रमुख लोगों और राजकीय उच्च विद्यालय अनाडेल के विद्यार्थियों ने लगभग 100 पौधे रोपित किए।

राज्यपाल ने सामाजिक गतिविधियों के साथ पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए शिमला प्रेस क्लब की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल हम सभी को समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करती है और क्लब कुशलतापूर्वक अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें कई उपहार दिए हैं और हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इनका संरक्षण करें। हमें पौधरोपण जैसे कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम समाज को सकारात्मक संदेश देते हैं।

राज्यपाल ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि शिमला प्रेस क्लब ने उनके नशा निवारण अभियान में भाग लेने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी की बढ़ती बुराई को रोकने के लिए सभी को मिल-जुलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर पुलिस विभाग के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रेस क्लब द्वारा इस दिशा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

इससे पहले प्रेस क्लब शिमला के अध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया।

हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देना एक सराहनीय पहल: राज्यपाल

शिमला/शैल। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय फागली और हिमाचल संस्कृत अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में संस्कृत पर एक नाटक 'भारत विजयम' का मंचन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विनोद शर्मा द्वारा निर्देशित कथाकार मथुरा प्रसाद दीक्षित के नाटक का मंचन किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा देकर प्रदेश सरकार ने बहुत ही सराहनीय पहल की है और अब हम सबको मिलकर संस्कृत को आगे बढ़ाना है। राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत के प्रयोग और प्रसार के लिए आम लोगों को संभाषण शिविरों में भाग लेने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राजभवन में भी संभाषण शिविर के माध्यम से संस्कृत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत एक बहुत ही समृद्ध भाषा है और इसके शब्द देश के हर राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों के साथ-साथ यहां की समृद्ध संस्कृति पर भी एक सुनियोजित ढंग से प्रहार किया था और इससे देश की एकता टूट गई। संस्कृत भाषा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा।

भारत में ब्रिटिश शासन से पहले भारत की आर्थिक समृद्धि और साक्षरता के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि हम हर तरह से संपन्न और समृद्ध थे। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए संस्कृत के उद्भव पर बल दिया।

इससे पहले, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा ने राज्यपाल को सम्मानित करते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिल सके। उन्होंने संस्कृत को श्रुति से आगे ले जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं और हाल ही में प्रदेश में दो नए संस्कृत महाविद्यालयों को अधिसूचित किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही प्रदेश का अपना संस्कृत विश्वविद्यालय भी होगा।

हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी के सचिव डॉ. केशवानंद कौशल ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इस अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व कुलपति पद्मश्री प्रो. अभिराज राजेंद्र मिश्र, सारस्वत अतिथि प्रो. केशव राम शर्मा, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय फागली के प्रधानाचार्य डॉ. मुकेश शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल से परिवीक्षाधीन आईएएस एवं एचएएस अधिकारियों ने भेंट की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वर्ष 2021 बैच एवं के हिमाचल प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के वर्ष 2022 बैच के परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर्ज़) अधिकारियों तथा संबद्ध सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भेंट की। ये परिवीक्षार्थी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलॉन शिमला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयनित होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने अधिकारियों से समर्पण, ईमानदारी और देशभक्ति की भावना के साथ समाजसेवा करने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं और व्यवहार ही उनकी पहचान है। उन्होंने कहा कि मन में सेवा भाव रखकर देशहित में कार्य करना चाहिए।

राज्यपाल ने कार्य संस्कृति, पर्यटन, उद्योग, पर्यावरण और प्रदेशहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचार साझा किए। उन्होंने अधिकारियों से अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने जीवन में सकारात्मक रहने की सलाह देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए।

हिपा के निदेशक ऋग्वेद ठाकुर, अतिरिक्त निदेशक ज्योति राणा तथा संयुक्त नियंत्रक विकास गुप्ता इस अवसर पर उपस्थित थे।

30 सितंबर को "डाक अदालत" का आयोजन

शिमला/शैल। चीफ पोस्टमास्टर जनरल, हि.प्र. सर्किल, शिमला, द्वारा सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के परिमण्डल कार्यालय तथा अधीनस्थ सभी प्रवर अधीक्षक/अधीक्षक डाकघरों के मण्डलीय कार्यालयों में 'डाक अदालत' 30 सितंबर को सांय 4:00 बजे आयोजित होनी निश्चित हुई है। इस दिन अदालत जनता की डाक सम्बन्धी शिकायतें सुनेगी।

यदि ऐसी कोई शिकायत हो तो उसे सहायक पोस्टमास्टर जनरल (जन शिकायत), कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, हि.प्र. सर्किल, शिमला-171009 को अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के प्रवर अधीक्षक/अधीक्षक डाकघर को 23 सितंबर तक अवश्य भेजें।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

मुख्यमंत्री ने 30 नई एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए 30 नई एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश

की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और एम्बुलेंस की निरन्तर आवश्यकता के दृष्टिगत यह सुविधा मरीजों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के दूरदराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों के घरद्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 25 दिसम्बर, 2010 को राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत यह राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में 46, वर्ष 2020 में 100 और वर्ष 2022 में 50 एम्बुलेंस जनता को समर्पित की है। इस प्रकार प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के अन्तर्गत 196 एम्बुलेंस प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त जन कल्याण के लिए वर्ष 2020 में 10 जीवनधारा स्वास्थ्य एम्बुलेंस भी समर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना के अन्तर्गत 10 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं और अभी तक जन कल्याण के लिए कुल 25 मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक वाहन प्रदान किए जा चुके हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 ने अब तक प्रदेश के 18,25,695 लाभार्थियों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 248 एम्बुलेंस के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश पुलिस को दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2021 के आंकड़ों में अपहरण और लापता व्यक्तियों का पता लगाने में देशभर में दूसरा स्थान हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम अपराध दर वाला शांतिपूर्ण राज्य है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को आधुनिक सुविधाएं एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली में अच्छे सुधार लाए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करके विभिन्न अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य पुलिस के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की।

जय राम ठाकुर ने कहा कि विगत साढ़े चार वर्षों के दौरान पुलिस कर्मियों के सैंकड़ों पद भरे गए हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई नए थाने और चौकियां भी खोली गई हैं। पुलिस बल में त्वरित आवाजाही सुनिश्चित बनाने के लिए लगभग 350 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण और ढांचागत विकास पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रहीः डॉ. राजीव सैजल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल की अध्यक्षता में क्षेत्रीय

आयुर्वेदिक चिकित्सालय शिमला की रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई।

इस अवसर पर डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति रही है और प्रदेश सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। क्षेत्रीय अस्पताल शिमला में भी सप्ताह भर चौबीसों घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त यहां आंखों के उपचार के लिए शलाक्य ओपीडी, लीच थैरेपी, अग्निकर्म व कुर्च कर्म, सोरेसिस उपचार सहित क्षार लेप इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इन उपचार सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सालय के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन व राज्य बजट के माध्यम से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट व अतरंग अनुभाग, नेत्र अनुभाग व प्रयोगशाला में आधुनिक यंत्र सहित अन्य उपकरणों पर 62.68 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। पंचकर्मा कक्ष के उन्नयन, रूक्ष संवेदन कक्ष व पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की खरीद इत्यादि पर 10 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय के शौचालयों के नवीनीकरण व दिव्यांगजनों के आवागमन के लिए सहायक उपकरणों पर 2.10 लाख रुपये और अग्निशमन सुरक्षा प्रबंधन पर 2 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

बैठक में अवगत करवाया गया कि इस चिकित्सालय के माध्यम से आयुष्मान तथा हिमकेयर योजनाओं के लाभ भी समय-समय पर पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 2019 से 2021 तक 556 लोगों को आयुष्मान भारत तथा 944 लोगों को मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

बैठक में शासी निकाय की पूर्व बैठक में अनुमोदित बजट से किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा तथा विभिन्न निर्णयों की कार्यान्वयन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों में रोगी कल्याण समिति की आय व व्यय ब्यौरा भी अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया। बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत कार्य के लिए 34 लाख रुपये तथा राजस्व कार्य के लिए 22 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया। बैठक में गैर सरकारी सदस्यों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक की कार्यवाही का संचालन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पूनम ने किया।इस अवसर पर उप सचिव आयुष मीना शर्मा, निदेशक आयुष विनय सिंह, अतिरिक्त निदेशक और शासी निकाय के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

बागवानी विकास परियोजना गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना गवर्निंग काउंसिल की बैठक मुख्य सचिव आर. डी. धीमान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति की सराहना करते हुए परियोजना की विभिन्न गतिविधियों सामुदायिक सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, एचपीएमसी एवं राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभाग को आयातित पौधों पर निर्भरता कम करने और सस्ते दामों पर उच्च गुणवत्ता वाले पौधें उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की नर्सरियों में उच्च गुणवत्ता वाले अधिक से अधिक पौधें तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बागवानी विभाग की नर्सरियों में उच्च गुणवत्ता बनाये रखने के लिए इनमें कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी ने परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि बागवानी विकास परियोजना की कुल लागत 1066 करोड़ रुपये में से अब तक 644 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

परियोजना निदेशक सुदेश कुमार मोक्टा ने परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि परियोजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 30 लाख पौधें आयात किए जा चुके हैं और बागवानी विश्वविद्यालय में लगाये गये पौधों से 5-6 गुणा पैदावार प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत 216 समूहों में सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत एचपीएमसी की 15 इकाइयों में सीए स्टोर, ग्रेडिंग लाइन्स एवं फल प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण एवं उन्नयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा परियोजना के तहत नौ मंडियों का निर्माण और उन्नयन किया जा रहा है।

बैठक में प्रधान सचिव (वन) रजनीश और बागवानी निदेशक डॉ. आर.के प्रुथी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में 19 लाख लोग सहकारिता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैंः सरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास, नगर नियोजन एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केन्द्रीय गृह एवं

सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया।

इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सहकारिता का भारत से पुराना नाता रहा है और हिमाचल में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव वर्ष 1892 में प्रदेश के ऊना जिला के पंजावर नामक स्थान में एक सहकारी सभा के गठन के साथ हो गया था। उन्होंने कहा कि देश के सहकारी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पहल 6 जुलाई, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने से हुई और प्रधानमंत्री ने देश को 'सहकार से समृद्धि' का मन्त्र भी दिया।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 19 लाख लोग सहकारिता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को बहुद्देशीय सेवा केंद्रों में बदलने सम्बन्धी योजना में केन्द्र द्वारा प्रदत्त 50 सभाओं के लक्ष्य के विपरीत 46 सभाओं को रूपांतरित कर दिया गया है और 19 अन्य सभाओं के रूपांतरण का कार्य प्रगति पर है। इन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए समुचित बजट प्रावधान करते हुए प्रदेश व जिला स्तरीय समितियों का गठन कर लिया गया है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए 97वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार प्रदेश के सहकारी कानून में कुछ बदलाव किये गए हैं। अब सहकारी सभाएं अपनी आम सभा में प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये ऑडिटर के पैनल में से ऑडिटर्स को चुन सकती हैं। इस से अधिक लोगों को रोज़गार मिलने के साथ ही सहकारी सभाओं के काम में पारदर्शिता रहेगी।

उन्होंने कहा कि देश में एफपीओ (कृषक-उत्पादक संगठन) क्रान्ति शुरू हुई है और हिमाचल भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। हिमाचल प्रदेश ने सहकारिता के इस नए रूप में युवाओं को जोड़ने की दृष्टि से युवा सहकार योजना के रूप में एक पहल की है। प्रदेश में कुछ जगहों पर केंद्रीय योजनाओं में चुने गए उत्पादों के अलावा सेब व अन्य फसलों के बागवान-किसानों को सहकारिता के इस नए रूप से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत बनने वाली समितियों में कम से कम 60 प्रतिशत युवा होंगे और समिति को चलने में मदद करने के लिए विभाग के इंस्पेक्टर अधिकृत किये गए हैं। इस कार्यक्रम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए एक कार्यबल का भी गठन किया गया है। अभी तक केंद्र की योजनानुसार प्रदेश में 16 नए एफपीओ बनाये गए हैं और 30 के लगभग एफपीओ बनाने का कार्य अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में हिमाचल में भी प्राथमिक सहकारी सभाओं की कवरेज बढ़ाने पर तेज़ी से काम चल रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 4881 सहकारी सभाएं पंजीकृत हैं जिनमें से 2178 प्राथमिक सहकारी सभाएं हैं।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण योजना भी तैयार की है। इसके लिए हिमकोफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में एफपीओ से सम्बंधित प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी तैयार किया है। प्रबन्धन समिति के सदस्यों को सहकारिता का प्रशिक्षण देने का काम राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर किया जा रहा है।

लगातार अच्छे विचार सोचते रहना ही बुरे विचारों को दबाने का एकमात्र तरीका यही है।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

वक्त की जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा

क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय की आवश्यकता बन गयी है? क्या इस यात्रा के लिये कांग्रेस का ही एक वर्ग मानसिक रूप से तैयार नहीं है? क्या भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का आहवान लोकतन्त्र को सशक्त बनायेगा? क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्षेत्रीय दलों को लेकर आया ब्यान एक स्वस्थ राजनीतिक संकेत है? क्या न्यायपालिका में भी एक वर्ग द्वारा परोक्ष/अपरोक्ष में हिन्दू राष्ट्र की वकालत करना सही है? यह कुछ सवाल है जो इस समय हर संवेदनशील, बुद्धिजीवी को कौंध रहे हैं। इन सवालों पर खुले मन मस्तिष्क से चिन्तन और चिन्ता करना आज की आवश्यकता बन चुका है। देश के हर व्यक्ति को यह सवाल प्रभावित करते हैं भले ही वह इनके प्रति सजग हो या न हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह यात्रा उस समय शुरू की है जब गुलाम नवी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर चले गये हैं। कांग्रेस से यह नेता उस समय बाहर गये हैं जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं का आरोप रहा है कि गांधी परिवार का नेतृत्व कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। इस परिदृश्य में इन नेताओं के पास अब वह अवसर था कि यह लोग स्वयं संगठन की अध्यक्षता के लिए अपनी दावेदारी का दावा पेश करते। लेकिन ऐसा करने की बजाये इन लोगों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुये संगठन छोड़ने का आसान रास्ता चुना। इससे स्वत: ही यह प्रमाणित हो जाता है कि इनके तार कहीं और से संचालित हो रहे थे। क्योंकि पिछले आठ वर्षो ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इस अवधि में राहुल गांधी ही सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष के निशाने पर रहे हैं। कोबरापोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में यह सामने आ चुका है कि राहुल गांधी को पप्पू प्रचारित करने के लिये मीडिया में कितना निवेश किया गया था। इन आठ वर्षो में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि सत्ता पक्ष के सामने आज तक पूरी ताकत के साथ खड़ा रहने वाला राहुल गांधी पहला नेता है। शायद राहुल गांधी की इस राजनीतिक दृढ़ता के कारण ही आज इस यात्रा के दौरान उनके पहरावे और यात्रा के प्रबंधों पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं।

इस परिदृश्य में यह तलाशना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज यह यात्रा वक्त की जरूरत क्यों बन गयी। इसके लिये अगर अपने आस पास नजर दौड़ायें तो सामने आता है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिये केन्द्रीय जांच एजेन्सियों का इस्तेमाल किस हद तक बढ़ा दिया है। इन एजेन्सियों के बढ़ते दखल ने इनकी विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। पिछले काफी समय से संघ प्रमुख डॉ. मनमोहन भागवत के नाम से भारत के नये संविधान के कुछ अंश वायरल होकर बाहर आ चुके हैं। लेकिन इस पर न तो केन्द्र सरकार और न ही संघ परिवार की ओर से कोई खण्डन आया है। बल्कि मेघालय उच्च न्यायालय के जस्टिस सेन के दिसंबर 2018 में आये हिन्दू राष्ट्र के फैसले और अब डॉ. स्वामी की संविधान से धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद शब्दों को हटाने के आग्रह की सर्वोच्च न्यायालय में आयी याचिका ने इन आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। क्या आज के भारतीय समाज में यह सब स्वीकार्य हो सकता है।

2014 के लोकसभा चुनावों से पहले अन्ना आन्दोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों को उछाला गया था क्या उनमें से एक भी अन्तिम परिणाम तक पहुंचा है? क्या आज भाजपा शासित राज्यों में सभी जगह लोकायुक्त नियुक्त है? क्या सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोग सुचारू रूप से कार्यरत हैं? क्या इस दौरान हुये दोनों लोकसभा चुनावों में हर बार चुनावी मुद्दे बदले नहीं गये हैं? इस दौरान नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक जितने भी आर्थिक फैसले लिये गये हैं क्या उनसे देश की आर्थिकी में कोई सुधार हो पाया है? क्या सार्वजनिक संस्थानों को प्राइवेट सैक्टर के हवाले करना स्वस्थ्य आर्थिकी का लक्षण माना जा सकता है? आज जब शिक्षा और स्वास्थ्य को पीपीपी मोड के माध्यम से प्राइवेट सैक्टर को देने की घोषणा की जा चुकी है तब क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि यह आवश्यक सेवाएं आम आदमी को सुगमता से उपलब्ध हो पायेंगी? कल तक यह कहा जा रहा था कि चीन हमारी सीमा में घुसा ही नहीं है परन्तु अब यह कहा जा रहा है कि चीन वापिस जाने को तैयार हो गया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय महत्व के हर मुद्दे पर लगातार गलत ब्यानी हो रही है और उसे हिन्दू-मुस्लिम तथा मन्दिर-मस्जिद के नाम पर नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। आज इन सवालों को आम आदमी के सामने ले जाने की आवश्यकता है और इस काम के लिये किसी बड़े नेता को ही भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस काम को अन्जाम देना होगा। राहुल गांधी की यात्रा से सता पक्ष में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उभर रही हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह यात्रा सही वक्त पर सही दिशा में आयोजित की गयी है।

ज़मीन का सबसे तेज जानवर चीता फिर लौटेगा

भूपेंद्र यादव
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री

शिमला। चीते की वापसी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और भारत एक बार फिर से ज़मीन के सबसे तेज जानवर का स्वागत करने का बेताबी से इंतजार कर रहा है, जिसकी गुर्राहट कभी ऊंचे पहाड़ों और तटों के सिवाए समूचे देश के जंगलों में प्रतिध्वनित होती थी। 17 सितंबर को चीते भारत में वापस लौटेंगे। जल्दी ही चीता मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में विचरण कर रहा होगा।

भारत में चीतों के न रहने के लिए असंख्य कारण जिम्मेदार रहे हैं, जिनमें पथ-निर्धारण, इनाम और शिकार के खेल के लिए बड़े पैमाने पर जानवरों को पकड़ना, पर्यावास में व्यापक बदलाव और उसके परिणामस्वरूप उनके शिकार के आधार का सिकुड़ना जैसे कारण शामिल हैं। ये सभी कारण मानव की कारवाइयों से प्रेरित हैं, और यह सिर्फ एक बात-प्राकृतिक दुनिया पर मनुष्य के पूर्ण प्रभुत्व-का प्रतीक हैं। इसलिए जंगल में चीते की दोबारा वापसी एक पारिस्थितिकीय गलती को सुधारने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दुनिया को दिए गए 'मिशन लाइफ' मंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मिशन लाइफ का उद्देश्य वास्तव में एक समावेशी दुनिया का निर्माण करना है, जहां मनुष्य का लालच हमारी वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के अस्तित्व की जरूरत को नहीं लांघता, अपितु जहां मनुष्य, जीव-जंतुओं सहित प्रकृति के साथ सद्भाव से रहते हैं।

विकास के पश्चिमी मॉडल ने इस धारणा को जन्म दिया कि मानव सर्वोच्च है और प्रौद्योगिकी की शक्ति से युक्त यह 'सर्वोच्च मानव' हर उस चीज को हासिल कर सकता है, जिस पर वह अपना दावा करता है। जब इस मॉडल को व्यवहार में लाया गया, तो मानव कहीं खो गए और इसके साथ ही उनके द्वारा अस्थायी रूप से अर्जित की गई समृद्धि की भावना भी गुम हो गई। इस मॉडल ने न केवल अनेक प्रजातियों को खतरे में डाला, बल्कि पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। युगों से भारत में हम 'प्रकृति रक्षति रक्षिता' पर विश्वास करते आये हैं। हमारी आजादी के बाद से देश ने केवल एक विशाल जंगली स्तनधारी को खोया है।

हम अपनी आबादी के आकार और विकास संबंधी जरूरतों के बावजूद बाघ, शेर, एशियाई हाथी, घड़ियाल और एक सींग वाले गैंडे सहित कई महत्वपूर्ण प्रजातियों व उनके पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने में सक्षम रहे हैं। पिछले कुछ वर्षो में भारत प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट एलीफेंट के साथ इन बेहद महत्वपूर्ण प्रजातियों की तादाद बढ़ाने में भी समर्थ रहा है।

जहां एक ओर बाघ वन प्रणालियों की एक प्रमुख अग्रणी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं चीता खुले जंगलों, घास के मैदानों और चारागाहों के शून्य को भर देगा। चीता की वापसी धरती के टिकाऊ पर्यावरण के निर्माण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है, क्योंकि एक शीर्ष परभक्षी की वापसी ऐतिहासिक विकासवादी संतुलन को बहाल करती है जो उनके पर्यावास की बहाली और शिकार के आधार के संरक्षण पर व्यापक प्रभाव डालती है। चीता उस विकासवादी स्वभाविक चयन प्रक्रिया का हिस्सा रहा है जिसके कारण हिरण और चिंकारा जैसी प्रजातियों में उच्च गति से अनुकूलन हुआ है। चीते की वापसी लुप्तप्राय प्रजातियों और खुले वन पारिस्थितिकी तंत्र सहित उसके शिकार-आधार की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, जो कि कुछ हिस्सों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं।

प्रोजेक्ट चीता उपेक्षित पर्यावासों को बहाल करने के लिए संसाधन लाएगा, जिससे उनकी जैव विविधता का संरक्षण होगा, उनके पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं और कार्बन को जब्त करने की उनकी अधिकतम क्षमता का उपयोग हो सकेगा। स्थानीय समुदाय को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा, क्योंकि चीते के लिए जिज्ञासा और सरोकारों के परिणामस्वरूप उत्पन्न पारिस्थितिक तंत्र से उनकी आजीविका के विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा और उनके रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

आज पूरी दुनिया विशाल मांसाहारी पशुओं और उनके पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो चुकी है। विशाल मांसाहारी पशुओं की संख्या में हो रही गिरावट के क्रम को रोकने या उलटने के लिए दुनिया भर में उनके पुन: प्रवेश और संरक्षण/ स्थानांतरण का उपयोग किया जा रहा है। चूंकि भारत, ग्रह के संरक्षक के रूप में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए पूरे दिल से आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसने भी चीते की वापसी का विकल्प चुना है, ताकि वह शीर्ष परभक्षी के रूप में चीते की वापसी के साथ उसके पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट का रुख पलट सके।

यूं तो चीते की पुन: वापसी कुनो में हो रही है, लेकिन उसकी तादाद में संभावित वृद्धि होने पर चीते को गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में प्रवेश कराया जा सकता है। इससे वन्यजीवन के अन्य रूपों और संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के साथ-साथ भारत की खोई हुई विरासत को पूरी तरह बहाल करने में मदद करेगी।

असाध्य रोग से ग्रस्त असहाय सन्नी और अंकुर को सरकार ने दिया 'सहारा'

शिमला। असाध्य रोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण बचपन से ही बिस्तर पर पड़े असहाय व्यीक्त और नेत्र रोग के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो चुके युवा की व्यथा की कल्पना मात्र से ही हर किसी का मन सिहर उठता है। कई वर्षो से यह दर्द झेल रहे हमीरपुर के निकटवर्ती गांव मझोट के 37 वर्षीय सन्नी और 31 वर्षीय अंकुर सोनी के परिजनों को न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के लिए बड़े-बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने तथा लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी सन्नी और अंकुर की सेहत में कोई सुधार न होने के कारण अब ये पूरी तरह अपने परिजनों पर ही आश्रित हैं।

पिछले साल कोरोना के कारण पिता की मृत्यु के बाद असहाय सन्नी और उसकी माता पर तो मानों मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी बुरी तरह टूट चुके सन्नी और अंकुर के परिजनों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की 'सहारा' योजना बहुत बड़ा सहारा साबित हो रही है। इस योजना के तहत इन दोनों को प्रतिमाह 3000 रुपये की राशि मिल रही है।

दरअसल, सन्नी और अंकुर की तरह गंभीर एवं असाध्य रोगों से ग्रस्त या किसी गंभीर दुर्घटना के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके लोगों के दुख-दर्द को समझते हुए ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में सहारा योजना आरंभ की। अधरंग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किन्सन, कैंसर, हैमोफिलिया, थेलेसेमिया, किडनी की गंभीर बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण या गंभीर दुर्घटनाओं के कारण अक्षम हो चुके लोगों तथा उनके परिजनों के लिए यह योजना बहुत बड़ी राहत लेकर आई है।

मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण लगभग 37 वर्षो से बिस्तर पर पड़े हमीरपुर के निकटवर्ती गांव मझोट के सन्नी की माता राज कुमारी ने बताया कि सहारा योजना के तहत अब सन्नी को हर माह प्रदेश सरकार की ओर से 3000 रुपये की धनराशि मिल रही है। यह धनराशि उनके लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हो रही है। प्रदेश सरकार का बार-बार धन्यवाद करते हुए राज कुमारी ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए बड़े-बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए और लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। परिवार की आर्थिक हालत भी बिगड़ती चली गई। पिछले वर्ष कोरोना के कारण पति की मौत के बाद तो उनकी मुसीबतें और भी बढ़ गई। लेकिन, सहारा योजना का लाभ मिलने के बाद अब उनका परिवार सन्नी की देखभाल बेहतर ढंग से कर पा रहा है।

गांव मझोट के ही एक युवा अंकुर सोनी को भी सहारा योजना के तहत प्रतिमाह 3000 रुपये मिल रहे हैं। बचपन में नेत्र रोग के कारण धीरे-धीरे अंकुर की आंखों की रोशनी चली गई है और वह 100 प्रतिशत अंधता का शिकार हो गए। साधारण परिवार से संबंध रखने वाले अंकुर के इलाज पर भी लाखों रुपये खर्च हुए। दोनों आंखों की रोशनी चले जाने के बाद अंकुर के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश सरकार की सहारा योजना अंकुर के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए अंकुर ने बताया कि प्रति माह 3000 रुपये मिलने से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है।

अंकुर और सन्नी की तरह ही प्रदेश में 20 हजार से अधिक असहाय लोगों को सहारा योजना का लाभ मिल रहा है। असाध्य रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए यह योजना नि:संदेह एक बड़ा सहारा बनी है। इस योजना के पात्र लोगों को अभी तक लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिये 8562.72 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी

शिमला। मत्स्य पालन, प्राथमिक उत्पादक क्षेत्रों में एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो हमारे देश के सामाजिक – आर्थिक विकास में, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक 'सनराइज सेक्टर' के रूप में माना जाने वाला यह क्षेत्र समानता, जिम्मेदारी और समावेशी तरीके से विशाल क्षमता के उपयोग की परिकल्पना करता है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 28 मिलियन जलीय कृषि किसानों और मछुआरों को रोजगार देता है और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला का लगभग दोगुना है।

विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर 2014 में मत्स्य पालन क्षेत्र में 'नीली क्रांति' का आहवान किया और सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने के लिए कई उपाय किए। कुछ प्रमुख केंद्रीय उपायों में शामिल हैं। (i) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए अलग मंत्रलय का गठन (ii) स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचे के साथ मत्स्य पालन विभाग का गठन (iii) नीति सुधार पहल (iv) महत्वपूर्ण अवसंरचना से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए वित्त वर्ष 2018 – 19 में 7,522.48 करोड़ रुपये के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष का निर्माण (एफआईडीएफ)। अब तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 4923.94 करोड़ रुपये मूल्य के प्रस्तावों की सिफारिश की गई है, जिनमें निजी लाभार्थियों के 120.23 करोड़ रुपये के 25 प्रस्तावों के साथ तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 20 मछली पकड़ने के बंदरगाह और 16 मछली उतारने के केंद्र (लैंडिंग) शामिल हैं।

'नीली क्रांति' योजना की सफलता को देखते हुए, भारत सरकार ने अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना – पीएमएमएसवाई की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपये के साथ अब तक का सबसे अधिक निवेश किया गया है। पीएमएमएसवाई को प्रधानमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य छोटे और कारीगर मछली किसानों की आय को दोगुना करना था। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि करना, घरेलू खपत और निर्यात आय में वृद्धि करना तथा मछली उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान में कमी लाते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र को समग्र रूप से बदलना है। पीएमएमएसवाई के शुभारंभ के दो साल पूरे होने पर आज यह आलेख लिखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

मछली उत्पादन बढ़ाने और कटाई के बाद फसलों के नुकसान को कम करने के लिये, आधुनिक मत्स्यपाल को अपनाना, मछली पकड़ने की गतिविधियों को उन्नत बनाना और कटाई के बाद फसलों का प्रबंधन जरूरी है। इसके लिये पीएमएमएसवाई मछुआरों, मछली पालने वालों और अन्य हितधारकों के कौशल तथा क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देती है, ताकि उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

देश में लागू हो जाने के बाद सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योजना का जोरदार स्वागत किया गया, तथा पिछले दो वर्षो के दौरान विभाग ने मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिये 8562.72 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह जानकारी देना प्रेरणास्पद है कि 2019 – 20 के दौरान मछली उत्पादन 141.64 लाख टन से बढ़कर अब 162.53 लाख टन हो गया है।

दूसरी तरफ, भारत का मछली निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 57,586.48 करोड़ रुपये पर कायम है। भारतीय निर्यात बाजार पर झींगा मछली का दबदबा है, विशेष तौर पर ''लिटोपेनियस वन्नामेई'' प्रजाति की झींगा मछली। पीएमएमएसवाई के तहत एक लाख करोड़ रुपये की कीमत का निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिये, विभाग टिलापिया, ट्राउट, पनगेसियस, कोबिया, पोमपेनो और कई अन्य प्रजातियों की गुणवत्ता तथा उत्पादन बढ़ाकर निर्यात बास्केट को विविधता देने पर ध्यान दे रहा है।

मत्स्यपालन क्षेत्र सम्बन्धी गतिविधियों और अब तक स्वीकृत परियोजनाओं ने लगभग 3.5 लाख लाभार्थियों को सीधे तौर पर और 9.7 लाख से अधिक लाभार्थियों को पूरी आपूर्ति श्रृंखला में रोजगार मुहैया कराया है। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/कम मछली पकड़े जाने वाली अवधि के दौरान केंद्रीय सहायता के रूप में 3000 रुपये/लाभार्थी/वार्षिक द्वारा कुल 6,77,462 सीमांत मछली पालकों तथा उनके परिवार वालों को आजीविका और पोषण समर्थन प्राप्त हुआ है।

मछली उत्पादन की निरंतरता बनाये रखने, मछली सम्बंधी सतत गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और जैव – परिवर्तन में तेजी लाने के लिये पीएमएमएसवाई ने समुद्र तथा नदी में मछली पालन कार्यक्रम को विशेष उप – गतिविधि के रूप में शुरू किया है।

अगले कुछ वर्षों में पीएमएमएसवाई का लक्ष्य रणनीतिक उपायों पर जोर देना है, जिसमें मछली पकड़ने की नौकाओं का बीमा, सतत मछली पालन को प्रोत्साहन देना, मछुआरों और मछली पालकों को समर्थन सेवायें प्रदान करना, प्रौद्योगिकी को शामिल करना, एकीकृत मत्स्य पार्क का निर्माण, मत्स्य सहकारिताओं/एफएफपीओ का गठन कुछ अहम घटक हैं।

पीएमएमएसवाई महिलाओं, अजजा/अजा समुदायों को जलकुंभी की खेती, सजावटी मछली पालन तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के जरिये वैकल्पिक आजीविका के अवसर तथा रोजगार प्रदान करने पर विशेष जोर देती है। मत्स्य क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका होती है और इसीलिये पीएमएमएसवाई महिला लाभार्थियों को 60 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, जिसमें महिला उद्यमियों को विशेष लाभ प्रदान करना तथा मत्स्य सेक्टर में उनके प्रवेश को प्रोत्साहन देना शामिल है। अब तक, महिला लाभार्थियों के लिये 1534.05 करोड़ रुपये कीमत की परियोजनाओं को स्वी ति दी गई है, जिनसे कुल 37,576 महिला लाभार्थियों को समर्थन मिलेगा।

निजी क्षेत्र की भागीदारी, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिये पीएमएमएसवाई ने उद्यमी मॉडल के तहत 100 करोड़ रुपये की निधि अलग से आबंटित की है। योजना के तहत युवा उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे आगे आयें और मत्स्य सैक्टर में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के जरिये समाधानों की पेशकश करें।

संस्थागत ऋण की सुविधा को सुलभ बनाने और कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018 – 19 से मछली पालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधाएं प्रदान की हैं। पात्र मछुआरों को परिपूर्ण करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों के साथ मिलकर देश भर में केसीसी के राष्ट्रीय स्तर के अभियान चलाए जा रहे हैं।

घरेलू खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), जोकि पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी लाभों को रेखांकित करने के लिए विभिन्न राज्यों में मछली उत्सव, पाक कला से जुड़ी संगोष्ठियां, प्रदर्शन यात्राओं के आयोजन में सहायता कर रही है। इन सबके अलावा, विभाग ने 10 अगस्त 2022 को 'फिश एंड सीफूड – 75 स्वादिष्ट व्यंजनों का संग्रह' नाम से एक कॉफी टेबल बुक जारी की है।

विभिन्न नीतिगत सुधारों और भविष्य में शुरू किए जाने वाले विशिष्ट कदमों सहित इस किस्म के कई उपायों के माध्यम से भारत सरकार स्थायी मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की दिशा में भारतीय मत्स्यपालन क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास कर रही है।

जनभागीदारी से टीबी मुक्ती की ओर भारत

मनसुख मांडविया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं खाद मंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा कहते हैं कि जब 130 करोड़ देशवासी एक साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो पूरा देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री का समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में जनभागीदारी के प्रतिअटूट विश्वास है। इस सामूहिक शक्ति और एकता की लहर से क्या हम नया भारत बना सकते हैं, जो 2025 में टीबी (क्षयरोग) मुक्त हो? प्रत्येक व्यक्ति का एक छोटा सा प्रयास भी एक 'जन – आंदोलन' को गति देता है। सरकार और जनता मिलकर जब कार्य करती है तो कोई भी अभियान शत – प्रतिशत सफल होता है। इसके उदाहरण हैं – स्वच्छ भारत अभियान, कोविड टीकाकरण अभियान और हाल ही में संपन्न 'हर घर तिरंगा' अभियान।

हम एक देश के तौर पर इसी सामूहिक जनभागीदारी के मंत्र के साथ 'टीबी मुक्त भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जब विश्व ने दुनिया से टीबी उन्मूलन के लिए वर्ष 2030 का लक्ष्य रखा, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी सामूहिक जनभागीदारी में विश्वास रखते हुए भारत को टीबी मुक्त करने के लिए दुनिया से पांच वर्ष पहले यानी कि वर्ष 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया। इसी लक्ष्य के संदर्भ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नि – क्षय पोषण योजना की शुरुआत की। जिसमें 2018 से जून 2022 तक 62.71 लाख टीबी रोगियों को 1,651 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसमें डीबीटी के माध्यम से टीबी रोगियों को 500 रुपये कि राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाना भी शामिल है, जिससे उन्हें अपनी पोषक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है।

मैं इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की माननीया राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का उल्लेख भी करना चाहूँगा, जिन्होंने टीबी से पीड़ित मरीज़ों को गोद लेने का अभियान चलाया और उस अभियान को अपार सफलता मिली।

उनके कार्यो से प्रेरणा लेकर टीबी के इस अभियान को आगे और मजबूती प्रदान करते हुए भारत सरकार ने 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' के तहत 'नि – क्षय 2.0' पोर्टल शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने 9 सितंबर, 2022 को किया है। यह पोर्टल टीबी मरीजों को सामुदायिक सहयोग देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इस पोर्टल पर जाकर समाज का कोई भी व्यक्ति या संस्था टीबी मरीजों की मदद 'नि – क्षय मित्र' बनकर कर सकता है।

इस अभियान का एक मुख्य भाग है टीबी मरीज़ों को गोद लेना। जिसका मूल उद्देश्य है कि हम समाज में टीबी मरीजों के प्रति प्रचलित भेदभाव को मिटा सके, टीबी से जूझ रहे लोगों के साथ हाथ मिलाना है, उनके लिए पोषण और सामाजिक समर्थन सुनिश्चित कर सकें तथा उनको सामान्य जीवन जीने में सहयोग कर सकें। टीबी मरीजों की सहायता हेतु 'नि – क्षय 2.0' पोर्टल (https://communitysupport. nikshay.in/) पर लॉग – इन कर सामुदायिक सहयोग कर सकते हैं। इस पहल के तहत कोई भी व्यक्ति, सहकारी संस्थाएं, कॉर्पोरेट जगत, गैर – सरकारी संगठन, राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि भीटीबी रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए गोद ले सकते हैं।

टीबी मरीजों को तीन प्रकार से मदद की जा सकती है। पहली मदद, उनके पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण आवश्यकता अनुसार पौष्टिक खाद्य सामग्री एक पोषण किट के रूप में उपलब्ध कराना। दूसरी मदद, अतिरिक्त लैब आधारित जांच में सहायता देना। तीसरा सहयोग, टीबी मरीजों को रोजगार प्राप्त करने के लिए जरूरी व्यवसायिक कौशल वर्धन द्वारा उनका क्षमता निर्माण करके रोजगार देने के लिए आगे आना। भारत के किसी भी जिले या ब्लॉक में टीबी रोगियों को आप न्यूनतम एक साल और अधिकतम तीन साल तक गोद लेकर उनका सहयोग कर सकते हैं।

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए मुफ्त दवाई, टीबी संबंधित विविध मुफ़्त जांच तथा कई प्रकार की अन्य मदद भी की जाती है। परंतु मेरा मानना है कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी की जनभागीदारी एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।

मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जन – आंदोलन को सही मायने में साकार करने के लिए इस मिशन का हिस्सा बनें और टीबी के खिलाफ देश की इस सामूहिक लड़ाई में सक्रिय भागीदार बनें। जैसे हम कोविड के विरुद्ध सशक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार टीबी उन्मूलन के लिए भी सामुदायिक समर्थन से एकसंगठित लड़ाई लड़ेंगे।

मैं आज आपके सामने रामायण का एक अंश साझा करना चाहूँगा। जब प्रभु श्री राम लंका जाने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे तब मदद के लिए एक गिलहरी भी आई। प्रभु श्री राम ने उसके इस छोटे से योगदान को भी सराहा।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में देशवासी उस गिलहरी से प्रेरणा लेकर इस ईश्वरीय कार्य से भारत को टीबी मुक्त बनाने में एक बहुत बड़ा सेवा कार्य कर सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इस मूलमंत्र से, मानवता का यह कार्य करने के लिए, इस जन – आंदोलन में आप अवश्य जुड़ेंगे और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर देंगें।

टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

कांग्रेस भाजपा के मिशन रिपीट को डिफ़ीट में बदलेगी:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस भाजपा के मिशन

रिपीट को डिफ़ीट में बदलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस ब्यान में जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रदेश में रीत व रिवाज को बदलेगी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह बौखलाहट में है और उन्हें यह एहसास हो चुका है कि उनकी सत्ता में वापसी संभव नही है इसलिए उन्हें बार बार अपने कार्यकर्ताओं से रीत व रिवाज बदलने की बात कहनी पड़ रही है।

प्रतिभा सिंह कहा है कि प्रदेश में भाजपा की ऐसी कोई भी उपलब्धि नही है जिसके लिये जयराम लोगों से वोट मांग सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। बागवान व किसान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। समाज का हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। लोग भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिये बेसब्री से चुनावों का इंतजार कर रहें है।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा का अधिकारियों के साथ भेदभाव, कर्मचारियों का उत्तपीडन मुख्य एजंडा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी अपनी उपेक्षा के चलते महामहिम को पत्र लिखने पर मजबूर है।भाजपा ने ब्यूरोक्रेसी को धड़े बाजी में बांट कर रख दिया है। मुख्यमंत्री की प्रशासन पर कमजोर पकड़ के चलते पूरी प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होकर रह गई है। आये दिनों अपने फैंसलों से पलटना जयराम सरकार की विशेषता रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री अब जितनी मर्जी घोषणाएं कर ले, वह न तो कभी पूरी होंगी और न ही इनके लिए कोई बजट है। जयराम कर्ज पर कर्ज लेते जा रहें है। अब 2500 करोड़ का और कर्ज लिया जा रहा है। सरकार के पास कर्मचारियों की देनदारी देने तक को पैसा नही है और मुख्यमंत्री अपने दौरो में जगह जगह रेवड़ियां बांटने में लगें है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ हो रहें शासकीय अन्याय को दूर करेगी और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन को लागू करेगी।

कांग्रेस बताए महिला सशक्तिकरण के लिए 70 सालों में क्या किया:इंदु गोस्वामी

शिमला/शैल। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्का लांबा जो मात्र एक माह पूर्व हिमाचल की प्रभारी नियुक्त हुई है वो जमीनी हकीकत से अवगत नहीं हैं वे न सिखाएं भाजपा को महिला कल्याण एवं उत्थान। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने अल्का लांबा पर पलटवार करते हुए कहा कि वो हिमाचल एक प्रभारी के नाते आई हैं । पर मुझे उन्हें एक नसीहत देनी है कि वे हिमाचल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। राजनैतिक लाभ लेने के लिए टिप्पणी करने से पहले वह प्रदेश में महिलाओं के लिए चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत अध्ययन करें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पदचिन्हों पर चलते हुए प्रदेश की जयराम सरकार ने आधी आबादी यानि महिलाओं को सबल बनाने के लिए असाधारण कार्य किया है। प्रदेश की सरकार ने पिछले पांच वर्षो में न सिर्फ घरेलु स्तर पर अपितु शिक्षा, कार्यक्षेत्र में भी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने का कार्य किया है। प्रदेश सरकार ने नारी शक्ति का सम्मान करते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जिनसे प्रदेश की जनता भली भांति अवगत है।

अस्थायी तौर पर पैराशूट द्वारा उतारे गये कांग्रेस के तथाकथित पदाधिकारी अपने अनर्गन ब्यान जारी करने से पूर्व एक बार प्रदेश की जनता से जमीनी हकीकत जान लें।

प्रदेश की जयराम सरकार ने इन पांच वर्षो के दौरान गृहिणी से लेकर सरकारी अथवा निजि क्षेत्र में कार्यरत हमारी महिला शक्ति के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है।

उन्होंने अलका लाम्बा के हिमाचल की जनता ने भाजपा को जीरो नंबर दिये हैं के जबाव में कहा कि कि वह भाजपा को नहीं कांग्रेस को दिये हैं। क्योंकि प्रदेश सरकार ने महिलाओं को साठ साल की उम्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किराए में 50% छूट व महिला सशक्तीकरण योजनाएं

शुरू की है। जबकि कांग्रेस ने 70 साल से महिलाओं का सिर्फ शोषण किया है।

प्रदेश सरकार ने सीएम कन्यादान की राशि 31 से 51 हज़ार कीए शगुन योजना शुरू की 31000 रूपये (बीपीएल), गृहणी सुविधा उज्जवला योजना हर साल 3 निशुल्क सिलेंडर, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 35 का अनुदान राशि का प्रदान की जा रही है। बेटी है अनमोल के अंतगर्त 21000 रूपये की एफ डी, स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण, कामगार कल्याण बोर्ड , बेटी के जन्म पर 51000 रूपये की एफ डी व पढ़ाई के लिए भी अनुदान दिया जाता है।

मेरा कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि वे कांग्रेस सरकार के समय महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई गई कोई पांच योजनाएं गिनवाएं। आज प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन से महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वे अपने मत का प्रयोग करके महिला विरोधी कांग्रेस को बाहर कर चुनाव में उनका असली चेहरा दिखाएगी और रिवाज बदल कर भाजपा को दोबारा प्रदेश की बागडोर सौंपेगी।

कांग्रेस 5 लाख युवाओं को देगी रोजगार

स्टार्ट–अप के लिए हर विधानसभा में स्थापित होगा 10 करोड़ का फंड

शिमला/शैल। कांग्रेस ने हिमाचल में पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी है। एआईसीसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एवं युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू ने शिमला में प्रैस कांफ्रैस में आने वाली कांग्रेस सरकार द्वारा युवाओं के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होंने भाजपा सरकार पर युवाओं को धोखा देने को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसके लिए सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ का स्टार्ट-अप फंड स्थापित किया जाएगा। इससे युवाओं को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। स्टार्ट-अप के लिए युवाओं को फंड के साथ फाइनासिंयल गाइडेंस, टैक्निकल हेल्प अन्य सहायता भी दी जाएगी।

कृष्णा अलावरू ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों ने विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार दिया है। पूर्व मनमोहन सरकार के समय में पूरी दुनिया में बड़ा वित्तीय संकट आया था, लेकिन उन्होंने उस दौर में भी रोजगार दिया गया, अंतराष्ट्रीय बाजार में मंहगा होने पर ही तेल 60-70 रुपए लीटर देकर मंहगाई को कंट्रोल किया। रोजमर्रा चीजों के दामों को भी बढ़ने नहीं दिया। मनमोहन सरकार ने मनरेगा जैसी बड़ी योजनाएं लाकर करीब 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। इसी तरह हिमाचल की पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार के समय में बेरोजगारी 3 से 5 फीसदी तक थी, वहीं मौजूदा जयराम सरकार के कार्यकाल में यह 20 फीसदी तक पहुंच गई।

युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं से धोखा किया है। जयराम सरकार ने विभागों में पड़े हजारों खाली पदों को नहीं भरा, वहीं एचपीयू और अन्य जगहों पर पिछले दरवाजों से अपने चहेतों की भर्तियां कीं। कई विभागों में खाली पदों को डाइंग कैडर में डाला।

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ राज्य कर एवं आबकारी विभाग का मेगा जागरुकता कार्यक्रम

एक साथ 38 स्थानों पर आयोजित जागरुकता कार्यक्रमों में 4400 व्यापारियों और उद्यमियों ने लिया भाग

शिमला/शैल । राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आम व्यापारियों, उद्यमियों, उद्योगपतियों और अन्य हितधारकों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में विस्तृत

जानकारी प्रदान करने के लिए आज एक प्रदेशव्यापी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया। विभाग के सभी 13 राजस्व जिलों के कुल 38 मुख्य स्थानों पर आयोजित इन जागरुकता कार्यक्रमों में करीब 4400 व्यापारियों, उद्योगपतियों, युवा उद्यमियों और अन्य हितधारकों ने भाग लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के इस प्रदेशव्यापी जागरुकता कार्यक्रम में रिकॉर्ड संख्या में भागीदारी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया।

प्रदेश सचिवालय के समिति कक्ष में आयोजित इस जागरुकता कार्यक्रम के समापन अवसर पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य निर्णायक भानु प्रताप सिंह ने विधिवत रूप से इस रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा।

इस अवसर पर विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए सुभासीष पन्डा ने कहा कि आम व्यापारियों और नए उद्यमियों को जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों और विशेषकर इसमें समय-समय पर होने वाले बदलावों के संबंध में अवगत करवाना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में विभाग विशेष प्रयास कर रहा है और सभी हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए नियमित रूप से जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

प्रधान सचिव ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित प्रदेशव्यापी जागरुकता कार्यक्रमों में आम व्यापारियों, उद्यमियों, उद्योगपतियों और अन्य हितधारकों ने काफी उत्साह दिखाया तथा एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भाग लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ सभी हितधारक भी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रतिभागियों से फीडबैक भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में विभाग प्रदेश भर के विभिन्न व्यापार मंडलों तथा अन्य हितधारकों के संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करके जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

इस अवसर पर राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त युनुस ने प्रदेशव्यापी जागरुकता कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों तथा जागरूकता कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त सुनील शर्मा, सहायक आयुक्त राकेश शर्मा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान 2,14,255 दावे व आक्षेप प्राप्त

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की लोक सभा और विधान सभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रथम अक्तूबर, 2022 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 16 अगस्त, 2022 को राज्य में स्थापित प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तथा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एडीसी/एसडीएम) तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में कर दिया गया है। प्रारूप मतदाता सूचियां 16 अगस्त से 11 सितम्बर, 2022 तक उपरोक्त स्थानों पर नि:शुल्क निरीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के दावे और आक्षेप निर्दिष्ट फार्म पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी।

उन्होंने बताया कि दावे अथवा आक्षेप दाखिल करने की इस अवधि में 11 सितम्बर, 2022 तक फार्म 6, 7 और 8 के माध्यम से कुल 2,14,255 दावे प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने के लिए फार्म 6 पर 1,50,261 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि मतदाता सूची से नाम हटवाने हेतु फार्म 7 पर 42,437 तथा मौजूदा निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार, ऐपिक प्रतिस्थापित करने, दिव्यांगजनों को चिन्हित करने व निवास स्थानान्तरण इत्यादि के लिए फार्म 8 पर 21,557 दावे अथवा आक्षेप प्राप्त हुए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्रदेश में सामान्य मतदाता संख्या 53,88,409 है, जिसमें 27,23,840 पुरुष तथा 26,64,549 महिला व 20 अन्य मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त सेवा अहर्ता मतदाताओं की संख्या 67,793 है, जिसमें 66,257 पुरुष व 1,536 महिला मतदाता हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 54,56,202 हैं, जिसमें 27,90,097 पुरुष, 26,66,085 महिला तथा 20 अन्य मतदाता शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि दावे व आक्षेपों का निपटारा 26 सितम्बर, 2022 तक किया जाएगा और फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 10 अक्तूबर, 2022 को किया जाएगा।

राज्यपाल ने किया नवनिर्मित ब्लड बैंक नालागढ़ की जनता को समर्पित

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो राज्य रेडक्रॉस के अध्यक्ष भी हैं, ने सोलन जिले के नालागढ़ में राज्य रेडक्रॉस के माध्यम से नवनिर्मित ब्लड बैंक को समर्पित किया। भारतीय रेडक्रॉस प्रबंधन समिति की सदस्य एवं राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। राज्यपाल ने इस अवसर पर जिला रेडक्रॉस तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारम्भ भी किया।

इस अवसर पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि पहली बार रेडक्रॉस ने सबके सहयोग से ब्लड बैंक स्थापित किया है और उनका प्रयास रहेगा कि भविष्य में प्रदेश के अन्य हिस्सों में ऐसे ब्लड बैंक स्थापित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इस ब्लड बैंक को स्थापित करने में औद्योगिक घराने के अनेक व्यक्तियों ने समाज सेवा की अपनी इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के माध्यम से प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन यूनिट भी स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

रेडक्रॉस के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों के सहयोग से रेडक्रॉस मानवता की सेवा में कार्यरत है। लोगों तक नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें, इसके लिए रेडक्रॉस प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में रेडक्रॉस भी अपना सहयोग दे रहा है।

राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉ. साधना ठाकुर ने कहा कि नालागढ़ में ब्लड बैंक की सुविधा मिलने से उनके प्रयास सफल हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां ब्लड बैंक की ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने रेडक्रॉस के माध्यम से कार्यान्वित विभिन्न

गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस के माध्यम से सुंदरनगर में डायलीसिस सेंटर, मंडी में फीजियोथेरेपी सेंटर तथा कुल्लू में हाल ही में महिलाओं के लिए पुनर्वास केंद्र, आईजीएमसी तथा के.एन.एच में सहायता केंद्र तथा बिलासुपर में रोटी मेकिंग मशीन स्थापित की गई है। इसके अलावा, मोबाईल हैल्थ यूनिट तथा करीब 30 से अधिक रोगी वाहन रेडक्रॉस ने भेंट किए हैं। उन्होंने रेडक्रॉस गतिविधियों को और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए लोगो से सहयोग की अपील की।

इससे पहले, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभासीष पन्डा ने राज्यपाल को सम्मानित किया।

स्वास्थ्य निदेशक डॉ. अनीता महाजन ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा स्वास्थ्य गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजन उप्पल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा, राज्यपाल के सचिव एवं महासचिव रेडक्रॉस राजेश शर्मा, बद्दी-बरोटीवाला -नालागढ़ विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋचा वर्मा, पुलिस अधीक्षक बद्दी मोहित चावला, नगर परिषद् की अध्यक्ष रीना शर्मा, पूर्व विधायक के. एल ठाकुर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने वर्ष 2023 को 'मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' के रूप में मनाने के

भारत के प्रस्ताव को पिछले वर्ष मंजूरी दी थी और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में अपनाया है। हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग और विभिन्न विश्वविद्यालयों ने मोटे अनाज की खेती के विकास और विस्तार के लिए विशेष पहल की है।

इसी कड़ी में राज्यपाल ने राजभवन में कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मोटे अनाज की खेती पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ किसानों के लिए आय का अच्छा स्रोत हो सकता है। मौसम की परिस्थितियों की दृष्टि से भी इसकी खेती काफी अनुकूल रहती है। राज्यपाल ने कहा कि किसान अकसर सीमांत भूमि पर ही मोटे अनाज की खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने, जहरीले उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न करके पर्यावरण-मित्र खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के किसानों ने पहले ही बड़े पैमाने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। इसी प्रकार मोटे अनाज की खेती के लिए प्रदेश सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर सकती है और इसके लिए एक उपयुक्त रणनीति निर्धारित की जा सकती है।

इस अवसर पर चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एच.के. चौधरी ने राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन के इतिहास के बारे में विस्तार से प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 की सांख्यिकी की वार्षिक पुस्तक के अनुसार राज्य में 6.71 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 5.88 हजार टन बाजरा की खेती की गई।

कृषि सचिव राकेश कंवर ने कहा कि कृषि विभाग मोटे अनाज के विकास के लिए नीति दस्तावेज तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती के माध्यम से इसकी उपज को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके औषधीय महत्व को देखते हुए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लघु चित्र के माध्यम लोगों को बाजरा की खेती के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजरा का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों एवं किसानों की भी पहचान की जाएगी।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

नर्सिज श्रेणी की मांगों पर सहानुभूतिपर्वूक विचार करेगी प्रदेश सरकार: डॉ. राजीव सैजल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार नर्सिज श्रेणी की मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है और अपने पौने पांच वर्ष के कार्यकाल में उन्हें विभिन्न लाभ और सुविधाएं प्रदान करने के

लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

यहां ट्रेंड नर्सिज एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश एवं सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज टीचिंग एसोसिएशन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने में नर्सिज श्रेणी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विशेष तौर पर कोरोना महामारी के समय नर्सो ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यकाल में नर्सो की रिकॉर्ड भर्तियां की गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना महामारी के दौरान नर्सो के लिए घोषित कोविड प्रोत्साहन राशि का शेष भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए।

बैठक में एसोसिएशन की ओर से परिचारिका (नर्स) श्रेणी को देय 13वें माह का वेतन वर्तमान के मूल वेतन के आधार पर प्रदान करने, नर्सो के लिए अस्पताल की परिधि में आवास उपलब्ध करवाने, सरकारी व निजी परिचारिका प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षारत प्रशिक्षुकाओं को आर्थिक एवं मेरिट आधार पर छात्रवृत्ति (स्टाईपेंड) प्रदान करने, स्टाफ नर्स पदनाम को केंद्र और पंजाब की तर्ज पर नर्सिंग ऑफिसर करने तथा नर्सिंग कॉलेज से संबंधित विभिन्न मागें रखीं गई।

डॉ. राजीव सैजल ने संघ के पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और इन पर समयबद्ध उचित निर्णय लिया जाएगा।

इस अवसर पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सुभासीष पन्डा ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक में ट्रेंड नर्सिज एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष ज्योति वालिया, अन्तरिम सचिव मनोरमा शर्मा, हरिप्रिया, नीलम गुप्ता, अनु सैणी तथा सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज टीचिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष सुनीता वर्मा, मुख्य सलाहकार संतोष मांटा, अतिरिक्त मुख्य सलाहकार किरण धर्मा, निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डॉ. अनीता महाजन तथा निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ. रजनीश पठानिया भी उपस्थित थे।

सभी प्रकार के विद्युत वाहनों की चार्जिंग के लिए एक समान पोर्ट निर्मित करने की आवश्यकता:बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने बेंगलुरू में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रलय द्वारा आयोजित विकास मन्थन कार्यक्रम के दूसरे दिन विशेष काउंसिल की बैठक में हिस्सा

लिया।

इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। परिवहन मंत्री ने इस अवसर पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से विद्युत वाहन निर्माता कंपनियों को सभी विद्युत वाहनों को चार्ज करने के लिए एक ही प्रकार के चार्जिंग स्टेशन अर्थात एक ही प्रकार की चार्जिंग प्रणाली विकसित करने के लिए निर्देश देने आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्युत वाहनों को अपनाने के लिए शिमला, बद्दी, मण्डी और धर्मशाला को आदर्श शहर घोषित करने की दिशा में कार्य करेगी। सरकार द्वारा वाहनों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 100 से अधिक विद्युत चालित बसें चलाई जा रही हैं तथा भविष्य में इनकी संख्या और अधिक बढ़ाने की योजना है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बैटरी चालित विद्युत वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए दक्षता से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार हिमाचल को विद्युत गतिशीलता, विकास और विद्युत वाहनों के निर्माण का एक वैश्विक केन्द्र बनाने पर विचार कर रही है।

बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल प्रदूषण मुक्त विद्युत संचालित और लागत प्रभावी अभिनव वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था के लिए नवोन्मेष प्रयास किए जा रहे हैं।

परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रोप-वे के विकास के लिए 26 अप्रैल, 2022 को भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं और पर्वतमाला योजना के तहत 60.6 किलोमीटर के लिए 2964 करोड़ रुपये लागत की 7 रोप-वे परियोजनाएं विकसित करने के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार से इन योजनाओं को शीघ्र शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने शिमला रोप-वे परियोजना को सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

मुख्यमंत्री का चेहरा कौन इस सवाल से कांग्रेस की एकजुटता पर होगा प्रहार

शिमला/शैल। हिमाचल कांग्रेस ने वर्तमान विधायकों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले पदाधिकारियों और पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष को टिकट देने की घोषणा करके भाजपा तथा आप पर जो पहल हासिल कर ली थी उससे जनता में यह सन्देश गया था कि पार्टी पूरी इमानदारी से एकजुट होकर वर्तमान सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए कार्यरत है। लेकिन एकजुटता का यह सन्देश उस समय ध्वस्त हो गया था जब पार्टी की वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद विपल्व ठाकुर का यह ब्यान आ गया कि अभी किसी का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है और इस ब्यान का कोई खण्डन भी नहीं आया। इससे पहले आनन्द शर्मा चुनाव संचालन कमेटी से त्यागपत्र देकर पार्टी की एकजुटता पर प्रश्नचिन्ह लगा चुके हैं। अब प्रदेश के कई चुनाव क्षेत्रों से एक दूसरे का विरोध होने के समाचार लगातार आने शुरू हो गये हैं। इसमें अब मण्डी से आश्रय शर्मा का भी नाम जुड़ने से स्थिति और जटिल हो गयी है। आश्रय ने भी प्रदेश नेतृत्व पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए अपना त्यागपत्र दिल्ली भेज दिया है। यही नहीं शिमला तक में कई टिकटार्थीयों ने यह ऐलान कर दिया है कि यदि उन्हें टिकट न मिला तो वह निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ ने तो चुनावी पोस्टर तक शहर में चिपका दिये हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व ऐसे लोगों के ऐसे कृत्यों के बारे में खामोश चला हुआ है और यही नेतृत्व की कमजोरी बनती जा रही है। इस समय कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ जयराम की सरकार और सुरेश कश्यप के संगठन से ही नहीं बल्कि दिल्ली बैठे नरेन्द्र मोदी तथा अमित शाह की नीतियों और भाषण बाजी से भी होगा यह मानकर चलना होगा। इसके लिये अभी तक कांग्रेस की कोई बड़ी तैयारी सामने नहीं आ रही है। क्योंकि नरेन्द्र मोदी की जुमलेबाजी के प्रभाव से ही 2014 में स्व. वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री होते हुये भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें जीत कर ले गयी थी तथा 2019 में इस जीत के अन्तर को और बढ़ा दिया था। वीरभद्र और सुखराम का सहयोग भी इसमें सेंध नहीं लगा पाया था। यह ठीक है कि उसके बाद इसी भाजपा और जयराम सरकार से कांग्रेस ने चारों उपचुनाव छीन लिये थे। लेकिन उस जीत में प्रदेश से ज्यादा राष्ट्रीय स्थितियों का बड़ा योगदान था और आज की तरह अपने घर में ऐसे विरोध के स्वर नहीं के बराबर थे। आज बहुत सारा विरोध प्रायोजित भी होगा और इसको पहचानना पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिये। इस समय राष्ट्रीय परिदृश्य जिस तरह के दौर से गुजर रहा है उससे राजनीति के सारे मानक बदल गये हैं। संविधान को बदलने के अपरोक्ष में प्रयास शुरू हो गये हैं। आर्थिकी लगातार कमजोर होती जा रही है और इसके कारण महंगाई तथा बेरोजगारी नियन्त्रण से बाहर जा चुकी है। लेकिन इसे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थीयों की हर जगह परेड करवाकर जन चर्चा से बाहर रखने का प्रयास किया जा रहा है। यह लाभार्थी खड़ा करने के लिये आम आदमी को किस तरह कर्ज के गर्त में धकेल दिया गया है इसे चर्चा में नहीं आने दिया जा रहा है। इस समय इन योजनाओं का असली चेहरा और कर्ज की वास्तविकता आम आदमी के सामने रखने की आवश्यकता है लेकिन इस दिशा में कांग्रेस के प्रयास नहीं के बराबर हैं। इसी कारण से आज भी कुछ लोग प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को कोस कर कांग्रेस छोड़ने के बहाने तलाश रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके प्रति कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता है। इस समय जो लोग टिकट न मिलने की सूरत में बगावती होकर चुनाव लड़ने की घोषणाएं कर रहे हैं उन्हें समय रहते बाहर का रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। आज जो लोग मण्डी में वहां की सांसद के दखल का ही विरोध करने पर उतर आये उन्हें संगठन का शुभचिंतक किस गणित से माना जा सकता है। इस समय प्रदेश नेतृत्व को सरकार के प्रति जितना आक्रामक होना चाहिये उसमें अभी बहुत कमी है। संगठन के बड़े चेहरों को सामूहिक एकजुटता का सन्देश देना सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि सता पक्ष इस एकजुटता को मुख्यमंत्री का चेहरा कौन के प्रश्न से उलझाने का प्रयास करेगी।

जैन की शिकायत पर ड्रग कन्ट्रोलर जनरल का प्रदेश के स्वस्थ सचिव को पत्र

शिमला/शैल। प्रदेश के दवा नियन्त्रक मरवाह के खिलाफ एक एम. सी. जैन लम्बे समय से राज्य सरकार से लेकर प्रधानमंत्री तक को गंभीर शिकायतें भेजते आ रहे हैं। प्रधानमन्त्री कार्यालय से यह शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय तक आगामी कारवाई के निर्देशों सहित आ चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव कार्यालय से भी यह शिकायतें आगामी कारवाई के लिये आगे भेजी जा चुकी हैं। लेकिन संयोगवश इन शिकायतों पर आज तक कोई कारवाई नहीं हो पायी है।

अब भारत सरकार के ड्रग कन्ट्रोलर जनरल ने इसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सचिव को कारवाई के लिए सीधे पत्र भेजा है। स्मरणीय है कि एम.सी. जैन ने छ: फार्मा कंपनियों को सीधे नाम से इंगित करते हुए 12 – 08 – 2020 के अपने पत्र में बहुत ही गंभीर आरोप लगाये हैं। बल्कि एक उद्योग के यहां से वह सामान चोरी होने का आरोप है जिसे शायद एक्साईज विभाग एक छापे में जब्त कर चुका था। कुछ उद्योगों के खिलाफ दूसरे राज्यों में तो कड़ी कारवाई होने की सूचना भी जैन की शिकायत में रही है। लेकिन इस सबके बावजूद राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई कारवाई न किया जाना कई सवाल खड़े करता है। इस परिदृश्य में ड्रग कन्ट्रोलर जनरल का यह पत्र महत्वपूर्ण हो जाता है।

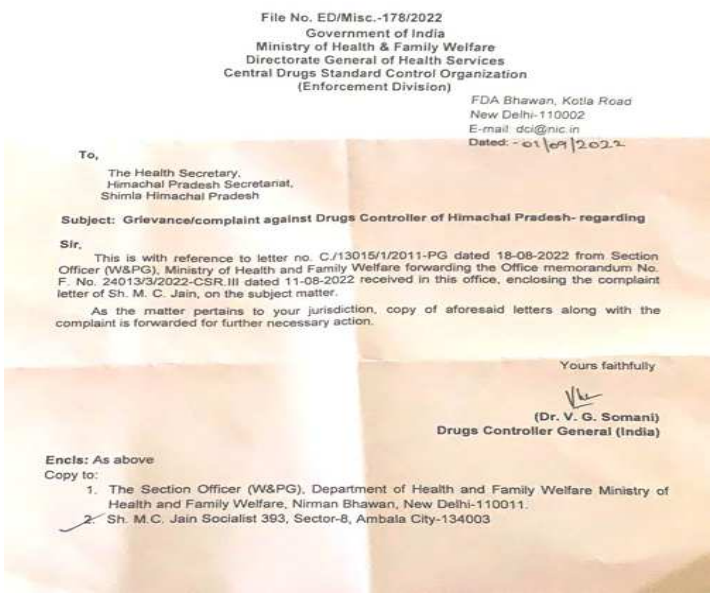

File No. ED/Misc.-178/2022
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Directorate General of Health Services
Central Drugs Standard Control Organization
(Enforcement Division)

FDA Bhawan, Kotla Road
New Delhi-110002
E-mail: dci@nic.in
Dated: - 01/09/2022

To,

The Health Secretary,
Himachal Pradesh Secretariat,
Shimla Himachal Pradesh

Subject: Grievance/complaint against Drugs Controller of Himachal Pradesh- regarding

Sir,

This is with reference to letter no. C./13015/1/2011-PG dated 18-08-2022 from Section Officer (W&PG), Ministry of Health and Family Welfare forwarding the Office memorandum No. F. No. 24013/3/2022-CSR.III dated 11-08-2022 received in this office, enclosing the complaint letter of Sh. M. C. Jain, on the subject matter.

As the matter pertains to your jurisdiction, copy of aforesaid letters along with the complaint is forwarded for further necessary action.

Yours faithfully

(Dr. V. G. Somani)
Drugs Controller General (India)

Encls: As above
Copy to:
1. The Section Officer (W&PG), Department of Health and Family Welfare Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.
2. Sh. M.C. Jain Socialist 393, Sector-8, Ambala City-134003

कितना सफल रहेगा आप का सुशान्त प्रयोग

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी की हिमाचल इकाई में कांगड़ा के पूर्व सांसद और धूमल सरकार में राजस्व मन्त्री रहे डॉ. राजन सुशान्त फिर से शामिल हो गये हैं। स्मरणीय है डॉ. सुशान्त 2014 में भी आप में थे और इसके टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन आगे चलकर स्थितियां बदली और सुशान्त ने आप से किनारा कर लिया। 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा बल्कि उसके बाद आया उप चुनाव भी लड़ा। इसी बीच अपना राजनीतिक दल भी पंजीकृत करवा लिया। ओ.पी.एस. को लेकर सरकार के खिलाफ संघर्ष भी छेड़ रखा है। **"हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी"** अपना राजनीतिक दल बनाकर प्रदेश को इस के बैनर तले चुनाव लड़ने का भरोसा भी दे चुके हैं। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि वह कारण सार्वजनिक हो जिनके चलते आप को छोड़ने की नौबत आयी थी और आज फिर से उसी में वापस जाने की बाध्यता खड़ी हुई। राजनीति करना और राजनीतिक दल बनाना या किसी में शामिल होना या उससे बाहर जाना सार्वजनिक जीवन का हिस्सा होते हैं। ऐसे में यह सब जानना आम आदमी का हक हो जाता है। फिर आम आदमी पार्टी बीते आठ वर्षो में हिमाचल में नेतृत्व को लेकर कई प्रयोग कर चुकी है। बल्कि इन्हीं कारणों से आप को भाजपा की बी टीम होने का तमगा भी मिल चुका है। क्योंकि जिस दिल्ली में विधानसभा पर तो उसका कब्जा लगातार पुख्ता होता गया परन्तु उसी दिल्ली में वह लोकसभा में दोनो बार शून्य रही। बल्कि नगर निगम भी उसके हाथ नहीं लग पाये। जिस दिल्ली मॉडल को देशभर में भुनाने के प्रयास हो रहे हैं आज उसी की व्यवहारिकता पर पंजाब में गंभीर सवाल उठने लग पड़े हैं और आप की ओर से उन पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। यही नहीं आज मुफ्ती की जो गारंटीयां आप घोषित करती जा रही है कांग्रेस और भाजपा ने तो उनकी संख्या भी कहीं अधिक बढ़ा दी है। ऐसे में जो मतदाता इन गारंटीयों के लिए आप पर भरोसा जतायेगा वह इन्ही के लिये कांग्रेस और भाजपा पर अविश्वास किस आधार पर कर पायेगा। इस समय आप के नेता दिल्ली से थोड़ी देर के लिये हिमाचल आकर गारंटीयां घोषित करके वापस चले जाते हैं। लेकिन प्रदेश का नेतृत्व बाद में उनकी आर्थिकी लोगों को समझा नहीं पाता है। बल्कि यही सदेश जाता रहा है कि हिमाचल को भी दिल्ली से ही संचालित करने की योजना चल रही है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि इस स्टेज पर आप का सुशान्त प्रयोग किसके पक्ष में कितना सफल रहता है।